बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-786/आ. नि श. दिनांक-16 जुलाई'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

(1) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(2) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना।

(3) जिला पदाधिकारी, रोहतास।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर जिसके अनुसार तीन दिव्यांग बच्चों के पिता द्वारा सपरिवार इच्छा मृत्यु की अनुमति माँगने से सम्बन्धित प्रेस कतरन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर जिसके अनुसार तीन दिव्यांग बच्चों के पिता द्वारा सपरिवार इच्छा मृत्यु माँगने सम्बन्धित प्रेस कतरन की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रकाशित समाचार के अवलोकन से विदित होता है कि रोहतास जिले के सझौली प्रखण्ड के घुलकार गाँव के निवासी श्री देवमुनी सिंह जो पेशे से कृषक है, के तीन पुत्रों का सही ढंग से ईलाज नहीं होने के कारण विकलांग हो गए। पुत्रों के ईलाज के क्रम में उनकी सारी पुश्तैनी जमीन बिक चुकी है। अब जीविका निर्वाहन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं अंकित रहने के कारण सरकार द्वारा प्रदत्त सारी योजना तथा आयुष्मान योजना का लाभ इनके परिवार को नहीं मिल पा रहा है, जिससे अत्यन्त बेबस और लाचार है।

समस्याओं के सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री, बिहार को अवगत कराते हुए इस सम्बन्ध में दिव्यांग बच्चों के पिता द्वारा सपरिवार इच्छा मृत्यु की अनुमति माँगी है। यह लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अत्यन्त ही गंभीर विषय है।

दिव्यांगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अध्याय-5 जो दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पुनर्वास आदि व्यवस्था से सम्बन्धित है, की कंडिका-24(1), 3(क) (ग) एवं (च) आदि पर किये गए प्रावधान के तहत मामले पर संज्ञान लेकर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाय ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-37 के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 05 प्रतिशत दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है एवं धारा-38 के तहत गंभीर दिव्यांगजनों के लिए उच्च सहायता की आवश्यकता को देखते हुए विशेष सहायता की आवश्यकता प्रतीत होता है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर दिनांक-27.07.2019 को पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी समस्याओं के निष्पादन हेतु आवश्यक लाभ दिलवाने हेतु प्रयास की आवश्यकता महसूस की गई है।

अनुरोध है कि प्रासंगिक मामले में लिए गए निर्णय से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 15.07.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

अनु0-यथोक्त।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-786/आ. नि श. दिनांक-16 जुलाई'19

प्रतिलिपि:-उप विकास आयुक्त, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 15.07.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0............

(SCD)/General Letter/Pg-335

o/c

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-786/आ.नि.श. दिनांक-16 जुलाई'19

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.07.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-786/आ.नि.श. दिनांक-16 जुलाई'19

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें।

15.07.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-786/आ.नि.श. दिनांक-16 जुलाई'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15.07.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

786/आ.नि.श.

... UDYOG PVT. LTD. | info@ucook.co.in | www.unitedektagroup.com

to D, EPWD, DM Rohtak, CS Rohtak, ADSS Rohtak

तिल-तिल मर रहे दिव्यांगों के पिता ने मांगी सपरिवार इच्छामृत्यु

दिव्यांग बच्चों के साथ परिवार

एनबीटी रिपोर्टर • [illegible] (रोहतक)

तिल-तिल कर मर रहे दिव्यांगों के पिता ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सपरिवार इच्छामृत्यु की मांग की है। दिव्यांग तीन संतानों के इलाज [illegible] नहीं किए जाने पर सपरिवार यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। पत्र में अपनी संतानों की व्यथा के साथ ही प्रशासनिक लापरवाही का भी जिक्र किया है। [illegible] प्रखंड के [illegible] निवासी [illegible] सिंह द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को स्पीड पोस्ट से आवेदन भेज सपरिवार इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी गई है। पत्र में उन्होंने कहा है कि बड़ा बेटा [illegible] 16 वर्ष का है। हाथ-पैर से पूरी तरह दिव्यांग है। 12 वर्ष की अवस्था में उसके हाथ-पैर अचानक सूखने लगे और डेढ़ साल के अंदर ही वह पूरी तरह पोलियोग्रस्त हो गया। पिता बड़े बेटे का इलाज करा ही रहे थे कि 10 वर्षीय [illegible] के हाथ-पैर भी बड़े भाई की तरह ही सूखने लगे। दोनों बेटे के इलाज में जो थोड़ी पुश्तैनी जमीन थी, वह भी बिक गई। स्थिति तब और बदतर हो गई, जब दो साल पूर्व तीसरा बेटा सात वर्षीय रमदीप भी उसी बीमारी की चपेट में आ गया। इन दिव्यांग संतान के पिता द्वारा सरकारी तंत्र की लापरवाही से भी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। पत्र में लिखा है कि झोपड़ीनुमा मकान में किसी तरह इस परिवार का गुजारा होता है। बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में नाम नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। पूरे तरह [illegible] इन दिव्यांग बच्चों के घर में शौचालय भी नहीं है।

[illegible]

"[illegible] है। ये तीन दस वर्ष के बाद [illegible] दिव्यांगता की दृष्टि से [illegible] नहीं की गई। [illegible] दिव्यांग बच्चों की [illegible] भी की गई। [illegible] सामने आती है [illegible] की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में इस परिवार का नाम नहीं जुड़ा है। [illegible] से भी बात की गई है।"

डॉ. जनार्दन शर्मा [illegible]

दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त दोषी करार

जागरण, सासाराम : दुष्कर्म से जुड़े छह साल पुराने एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम [illegible] प्रसाद मिश्रा की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अभियुक्त श्रीराम साह शिवसागर थाना क्षेत्र के मलावर गांव का निवासी है। शिवसागर बड्डी थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इस पर 18 मार्च 2013 को रात लगभग दस बजे एक घर में घुस 18 वर्षीया युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप था। इस मामले में सजा के बिंदु पर कोर्ट आगामी 16 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।

दहेज प्रताड़ना में एक वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, सासाराम : दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को एसडीजेएम राघवेंद्र नारायण सिंह की अदालत ने एक अभियुक्त को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त शाहनवाज अहमद उत्तरप्रदेश के [illegible] का निवासी है। इसके विरुद्ध नोखा के अब्बास [illegible] कोर्ट में 2007 में परिवाद दर्ज कराया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी पुत्री रेहाना की शादी 2006 में अब्बास के साथ कराई थी। शादी के बाद से [illegible] रुपये के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और 10 [illegible] 2007 को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था।

DOON BUSINESS SCHOOL
Dehradun - A Safe, Beautiful, Cosmopolitan Student City

LAST CALL TO APPLY TO ONE OF THE TOP RANKED INSTITUTION OF INDIA

MA Mass Comm
BA (Hons.) Mass Comm
Additional Certification in Acting and Movie Making

M.Sc. Agriculture
B.Sc. Agri/Forestry

BBA+MBA (5 Yr Integrated)
B.Com. (Hons.) + CA (CPT & IPCC)
BCA (SAP & Big Data Analy...
PGDM+SAP / PGDM ...
MBA / MBA-IB

DBS ADVANTAGE
IN-CAMPUS HOSTEL FOR BOYS & GIRLS
EXCELLENT SPORTING INFRASTRUCTURE
MERIT AND NEED BASED SCHOLARSHIPS
STUDENTS FROM 23 STATES AND 5 COUNTRIES

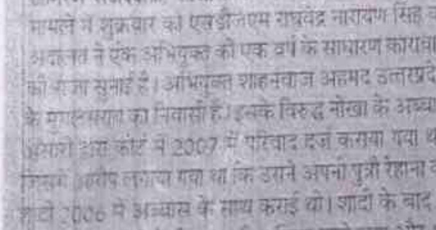

गाँव - [illegible], ब्लॉक - [illegible], Distt - Rohtak

Gmail

O/o State Commissioner Disabilities Govt. of Bihar <scdisability2008@gmail.com>

(no subject)

1 message

Dr Shivajee Kumar <shivajee100@gmail.com>
To: scdisability2008@gmail.com

Sent 15.07.19

Sun, Jul 14, 2019 at 5:57 PM

04 | patna | hindustantimes

Broke and broken, father of 3 children pleads for euthanasia

ON THE BRINK Family writes to PM, says the government has failed to provide help

Prasun K Mishra

CHHULKAR (SASARAM): A penurious family in Bihar's Sasaram town in Rohtas district, pleading for euthanasia, has written a letter to Prime Minister Narendra Modi as the government has failed to arrange for the treatment of its three sons suffering from rare congenital muscular disease that has left them paralysed at juvenescent ages.

The landless farmer, Devmuni Singh Yadav, resident of Chhulkar village, says that he has lost everything he had in the treatment of his three sons — Mantosh, 14, Dhantosh, 11 and Ramtosh, 7, — but to no avail as the disease requires treatment at specialised hospital in the metros and he doesn't have the resources.

Politicians and administrative officials, he rues, have only been giving him false assurances.

The poor farmer, forced to live in a thatched hutment along with his wife, daughter and the three physically impaired sons after he sold all his belongings including the 10 katha of ancestral cultivable land and 4 decimal homestead land, said that none in his family wants to lead this cursed life anymore and hence they have written a letter to the PM for the permission to end it.

Yadav's saga is indeed heart rendering. Life was happy for him and his family of six members till 2012 when the eldest son, Mantosh then eight, began undergoing unusual changes in his hands and feet. "They started becoming thinner and weak eventually rendering him bed

The farmer lives in a thatched hutment in Bihar's Sasaram town along with his wife, daughter and the three physically impaired sons. HT PHOTO

> The biggest problem is unavailability of a toilet. We lift the children on our shoulders and take them to the nearby fields to attend to nature's call, at least twice a day.
>
> DEVMUNI SINGH YADAV, Farmer

scribed several costly tests. Having exhausted his money, the poor man had no option then to return without completing the treatment. According to doctors, the blood circulation to the veins in the patient's body had stopped and required longer treatment.

Six months later, while he was still struggling with the treatment of his elder son, Yadav's sec-

THE FAMILY HAD SOLD ALL THE LAND, ORNAMENTS, AND PRECIOUS BELONGINGS TO PAY ₹1 LAKH BANK LOAN AND ₹4 LAKH LOAN TAKEN FROM VILLAGERS ON MUCH HIGH RATES OF INTEREST

doctors and exorcists with his two handicapped sons when he encountered yet another setback in 2017.

The youngest of the three sons, Ramtosh, also developed the same symptoms and became handicapped within six months. By now, the family had sold all the land, ornaments, and precious belongings to pay ₹1 lakh bank

standing on five feet high mud walls at the eastern end of remote Chhulkar village, the entire family was struggling with keeping away the rain water entering into their home. The floor was about one and half feet low than the muddy lane. It was raining since three days and roof was leaking. Threat of the dilapidated house caving in loomed large.

Yadav, 55, and his disabled sons were sitting on a mat on the soiled floor. Wife Anita and daughter Madhu, 16, were busy in keeping the floor dry and checking water from entering into the 'house'. They were using plastic sheets to save the one room house from caving.

Yadav rued since his family is not included in the BPL list, they are not enrolled in ambitious Ayushman Bharat scheme. Hence, they are deprived of the

local quacks and doctors at Sasaram besides a physiotherapist at Dehri. But recovery remained elusive," Yadav said.

After arranging some money, he then took the boy to BHU at Varanasi where doctors pre-

same symptoms. Soon his hands and feet too stopped working. Burdened with another patient at home, the poor man sold off his 10 kotha ancestral land at throwaway price to meet the medical emergency. He was running to

villagers on much high rates of interest. Rendered penniless, the family moved to a thatched hutment, which is deprived of basic amenities like toilet, water and a proper roof overhead.

When this correspondent reached Yadav's dwelling, 38km distance from Sasaram, the 10/8 feet room thatched hutment

He says, "The biggest problem is unavailability of a toi[illegible]. We could not arrange money for its construction. My wife, A[illegible], daughter Madhu, 16, and [illegible] lift the three disabled children on our shoulders and take them to the nearby fields at least twice a day. We also have to clean their bodies after the morning and evening ablutions."

Two of the elder brothers were getting disability pension of ₹400 since last year and 5kg ration for per member under Khadya Suraksha scheme after local journalist raised the issue before authorities. "But it is like a drop in the ocean," Yadav said.

EAST CENTRAL RAILWAY

E-TENDER NOTICE

Open E-Tender Notice No. 01Optg-SEE-19-20. The DRM (Optg.)/SEE for and on behalf of the President of India invites Open E-Tenders for the following works. The last date of online E-tendering is 09.08.2019 up to 13.00 hrs. All information and tender documents related to E-tender is available on website-www.ireps.gov.in.

1. Name of work with item no. : 1. Hiring of One Commercially registered Non-AC

EAST CENTRAL RAILWAY

E-TENDER NOTICE

e-Tender No. 2019/WP/ENGG/R-BLOCK/WT-04 (Open)

e-tender (open) are invited on behalf of the President of India with following details.

1. Name of the work with its location : Provision of boundary wall, gate, loading, unloading, stacking, and transporting of P.Way materials in connection with contruction of office of

EAST CENTRAL RAILWAY

E-TENDER NOTICE

E TENDER NOTICE NO. SG-684-03-Tele-2019-20 Dhanbad, date 09.07.2019. E Tender is invited on behalf of the President of India for the undermentioned work.

1. Name of the work : Renovation of Barkakana Control Office including Stations in Barkakana-Hazaribagh Town-Koderma